

आयकर आयुक्त, मद्रास

बनाम

आंध्र चेंबर ऑफ कॉमर्स

1 अक्टूबर, 1964

(के. सुब्बा राव, जे. सी. शाह और एस. एम. सिकरी जी.)

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (11 of 1922), धारा 4(3)(i)-धर्मार्थ उद्देश्य का अर्थ-व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देने का कंपनी का उद्देश्य, धर्मार्थ है या नहीं-व्यापार को प्रभावित करने वाले कानून का समर्थन या विरोध करना आदि-उद्देश्य राजनीतिक है या नहीं।

निर्धारिती कंपनी-आंध्र चेंबर ऑफ कॉमर्स-का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और विकसित करना था। इसके पास एक इमारत थी, जिसमें उसके कार्यालय थे, और इसके उपयोग में नहीं आने वाले हिस्से किरायेदारों को दे दिए गए थे। आयकर कार्यवाही में कंपनी ने भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 4(3)(i) के तहत किराये की आय के संबंध में छूट का दावा किया। यह दावा निर्धारण और अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा नकार दिया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने माना कि कंपनी एक धर्मार्थ संस्थान है और इसकी संपत्ति से होने वाली आय धारा 4(3)(i) के तहत छूट प्राप्त है।

राजस्व ने विशेष अनुमति द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील की।

अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि संपत्ति धारा 4(3)(i) के अर्थ के भीतर धर्मार्थ उद्देश्य के लिए कंपनी के पास नहीं थी, क्योंकि कंपनी के उद्देश्य अस्पष्ट थे, और संघ के ज्ञापन और संघ के लेखों में परिकल्पित लाभ आम तौर पर जनता के लिए नहीं होकर केवल कंपनी के सदस्यों के लिए था, और यह कि कंपनी के उद्देश्य राजनीतिक थे और इस आय को राजनीतिक उद्देश्यों हेतु प्रयोग किये जाने का विकल्प कम्पनी के लिए क्योंकि उसके लिए पूरी आय को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विनियोजित करना खुला था।

(i) अधिनियम में परिभाषित धर्मार्थ उद्देश्य शब्द समावेशी था न कि विशिष्ट। इसमें सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य शामिल थे। निर्धारिती कंपनी का उद्देश्य-देश में व्यापार और वाणिज्य को सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता हेतु बढ़ावा देना था क्योंकि इससे ना केवल व्यापारी वर्ग का वरन बल्कि पूरे देश को इससे लाभ होना था। यह आवश्यक नहीं है कि इस लाभ में समस्त मानव जाति शामिल हो किन्तु यदि इरादा जनता के एक वर्ग को लाभ पहुंचाना है जो कि एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है तो यह पर्याप्त है।

(ii) कंपनी के उद्देश्यों में कुछ भी अस्पष्ट नहीं था। सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य जैसे कि व्यापार, वाणिज्य को बढ़ावा

देना, संरक्षित करना, सहायता करना और प्रोत्साहित करना, उन तरीकों या चरणों को निर्दिष्ट करना जिनके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है या सुरक्षित किया जा सकता है, वैध होने के लिए मान्य नहीं है।

(iii) यह तर्क कि कम्पनी का यह कोश केवल आंध्र प्रदेश के व्यापारी वर्ग के लाभ के लिए ही विनियोजित किया जाना था, किसी जांच का आधार नहीं हो सकता था।

(iv) यह नहीं कहा जा सकता कि कोई उद्देश्य केवल इसलिए धर्मार्थ नहीं रह जाएगा कि वह सार्वजनिक कल्याण को सुरक्षित करने का इरादा रखता है यदि उसमें वाणिज्य, व्यापार या निर्माण को प्रभावित करने वाले कानून का समर्थन या विरोध करने के लिए कदम उठाना शामिल है। यदि प्राथमिक उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों की उन्नति करना है, तो वह धर्मार्थ ही रहेगा, भले ही उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रासंगिक प्रविष्टि को शामिल किया गया हो, जैसे कि उस उद्देश्य से संबंधित कानून का समर्थन या विरोध करना। जापन और संघ के लेखों में उल्लिखित उद्देश्य यह था कि निर्धारिती वाणिज्य, व्यापार या निर्माण को प्रभावित करने वाले विधायी या अन्य उपायों का समर्थन या विरोध करने के लिए कदम उठा सकता है। इस तरह के उद्देश्य को विशुद्ध रूप से सहायक या गौण माना जाना चाहिए न कि प्राथमिक उद्देश्य।

ट्रिब्यून के ट्रस्टियों के मामले में, 7 आई.टी.आर. 415 और अखिल भारतीय चरखा संघ बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे, 12 आई.टी.आर. 482, पर भरोसा किया गया, पेम्सेल बनाम आयकर के विशेष उद्देश्यों के लिए आयुक्त, और बोमन बनाम सेक्युलर सोसाइटी लिमिटेड, (1917) ए.सी. 406, का संदर्भ दिया गया। रेक्स बनाम आयकर के विशेष आयुक्त (एक्स-पार्टे इन्कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ प्रिपेरेटरी स्कूल्स) 10 टी.सी. 73, इंग्लैंड रेवेन्यू के आयुक्त बनाम इंग्लैंड और वेल्स के ईसाई चर्चों की टेम्परेंस काउंसिल, 10 टी.सी. 748, और लक्ष्मण बालवंत भोपटकर डॉ. धनंजय रामचंद्र गाडगिल बनाम धर्मार्थ आयुक्त, बॉम्बे, (1963) 2 एस.सी.आर. 625, को भिन्न बताया गया है।

नागरिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 941-946 of 1963. मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 22 फरवरी, 1961 को मामले में संदर्भित संख्या 121 of 1956 में पारित निर्णय के खिलाफ अपील।

के. एन. राजगोपालाचार्य शास्त्री, आर. एच. डेबर और आर. एन. सचदेव, अपीलकर्ता के लिए (सभी अपीलों में)।

ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री, के. राजेंद्र चौधरी और के. आर. चौधरी, प्रतिवादी के लिए (सभी अपीलों में)।

न्यायालय का निर्णय शाह जे. द्वारा दिया गया।

आंध्र चैंबर ऑफ कॉमर्स-जिसे इसके बाद में 'निर्धारिती' कहा जाएगा-

भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 की धारा 7 के तहत निगमित एक कंपनी है। निर्धारिती को मद्रास सरकार के आदेश से अधिनियम की धारा 26 के तहत अपने नाम से "सीमित" शब्द को हटाने की अनुमति दी गई थी। निर्धारिती के ज्ञापन और संघ के लेखों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(a) भारत के व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, मद्रास प्रांत में और विशेष रूप से आंध्र देश में।

(b) भारत में व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के विकास में सहायता, प्रोत्साहन और सहायता करना, जिसके पूंजी का अधिकांश भाग भारतीयों द्वारा प्रदान किया गया हो या जो भारतीयों के प्रबंधन में हो।

(c) भारत या उसके किसी भी भाग के सामान्य व्यावसायिक हितों की रक्षा करना और विशेष रूप से भारत में व्यापार, वाणिज्य या निर्माण में लगे आंध्रों के हितों की रक्षा करना और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश।

ऐसी अन्य सभी चीजें करना जो व्यापार, वाणिज्य, उद्योगों और विनिर्माण के संरक्षण और विस्तार के लिए या उपरोक्त उद्देश्यों या उनमें से किसी की प्राप्ति के लिए सहायक हो।

(d) से (x) तक के प्रावधान मुख्य उद्देश्यों के सहायक हैं।

ज्ञापन और संघ के लेखों के प्रावधान 4 के अनुसार, यह प्रावधित किया गया था कि निर्धारिती की आय और संपत्ति को उसके उद्देश्यों को

बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से लागू किया जाएगा जैसा कि उसमें निर्धारित किया गया है और इसका कोई भाग लाभांश, बोनस या अन्यथा किसी भी तरह से लाभ के रूप में उसके सदस्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

2 दिसंबर, 1944 को निर्धारिती ने एक इमारत खरीदी और उसमें पर्याप्त बदलाव, परिवर्धन और सुधार किए। निर्धारिती ने 14 मई, 1947 को अपने कार्यालयों को उस इमारत में स्थानांतरित कर दिया और उपयोग में न आने वाले हिस्से को किरायेदारों को दे दिया।

निर्धारिती की आय उसके सदस्यों से एकत्रित सदस्यता शुल्क, दान और इमारत से प्राप्त किराए से होती है। निम्न तालिका स्तंभ 3 और 4 में उस आकलन वर्षों के लिए सभी गतिविधियों के संबंध में किए गए निर्धारिती की आय (किराये की आय के अलावा) से अधिक व्यय की शुद्ध अधिकता और आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 9 के तहत अनुमेय वैधानिक कटौती के बाद संपत्ति के शुद्ध वार्षिक मूल्य को निर्धारित करती है, जिसके संबंध में इस समूह में अपील में विवाद उत्पन्न होता है:

पिछला वर्ष (कलेण्डर वर्ष)	मूल्यांकन वर्ष	रूपये	शुद्ध आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)

1947	1948-49	3,400	7,431
1949	1950-51	6,154	7,139
1950	1952-53	6,928	5,266
1952	1953-54	5,740	10,173
1953	1954-55	8,072	13,672

मद्रास, सिटी सर्कल । के दूसरे अतिरिक्त आयकर अधिकारी के समक्ष निर्धारण कार्यवाही में यह तर्क दिया गया था कि -

(i) निर्धारिती धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित एक संस्था थी और इसलिए आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 4(3)(i) के तहत उसकी आय से छूट प्राप्त थी;

(ii) निर्धारिती के भवन से होने वाली किराये की आय पर व्यापार लाभ कर नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि यह संपत्ति धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही थी। निर्धारिती के भवन का वार्षिक मूल्य आकलनीय नहीं था क्योंकि निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 4(3)(i) के अर्थ के भीतर एक धर्मार्थ संस्था थी। वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया गया था कि यदि वार्षिक मूल्य को आकलनीय माना जाता है तो व्यय की अधिकता को आय के विरुद्ध मुजरा किया जाना चाहिए। आयकर अधिकारी ने निर्धारिती के तर्कों को खारिज कर दिया और शुद्ध वार्षिक मूल्य के

आधार पर छह निर्धारण वर्षों में संपत्ति से अपनी आय का आकलन किया, जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा आय से अधिक व्यय को (किराए के अलावा) 'ऋण' खाते में डाले बिना वार्षिक मूल्य में निर्धारण हेतु शामिल कर लिया गया। निर्धारिती ने निर्धारण के सभी आदेशों के खिलाफ अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील की। अपीलीय सहायक आयुक्त ने माना कि निर्धारिती एक धर्मार्थ संस्था नहीं है, इसलिए विचाराधीन आय धारा 4(3)(i) के तहत छूट प्राप्त नहीं है। उन्होंने वैकल्पिक तर्क को भी खारिज कर दिया, क्योंकि उनके विचार में, निर्धारिती की कोई विशिष्ट लाभ कमाने वाली गतिविधि नहीं थी, जिससे होने वाले नुकसान को उसकी अन्य आय के विरुद्ध मुजरा किया जा सके। फिर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की गई।

न्यायाधिकरण ने माना कि निर्धारिती धारा 4(3)(i) के अर्थ के भीतर आयकर का भुगतान करने की देयता से मुक्त नहीं है, क्योंकि निर्धारिती की गतिविधियां प्राथमिक रूप से उसके सदस्यों के लाभ के लिए अभिप्रेत थीं और "केवल सभी घटक सदस्यों की ओर से सामूहिक कार्रवाई को शामिल किया है" जिसे "यह नहीं कहा जा सकता कि उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यापार या व्यवसाय या व्यवसाय का परिणाम है"।

निर्धारिती के अनुरोध पर न्यायाधिकरण ने उच्च न्यायालय को निम्नलिखित प्रश्न भेजे:

"(1) क्या निर्धारिती के स्वामित्व वाली संपत्ति से उपर्युक्त आय पूर्वोक्त छह निर्धारण वर्षों के लिए धारा 4(3)(i) के तहत छूट प्राप्त है?

(2) यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या निर्धारिती की गतिविधियां एक व्यापार या व्यवसाय के रूप में होती हैं, जिसका लाभ या हानि धारा 10 के तहत आकलनीय है?"

उच्च न्यायालय ने पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया और दूसरे प्रश्न पर औपचारिक उत्तर दर्ज नहीं किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, आयकर आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 66ए(2) के तहत संदत प्रमाण पत्र के साथ उच्च न्यायालय के इन आदेशों की अपील की गई।

हम इस समूह की अपीलों में 1948-49 से 1954-55 के वर्षों में निर्धारिती की आय के आकलन से संबंधित हैं।

अधिनियम 25 of 1953 द्वारा 1 अप्रैल, 1952 से प्रभावी होने से पहले धारा 4(3)(i) के निम्नलिखित रूप में पढ़ने के साथ, मूल्यांकन वर्ष 1952-53

के अपवाद के साथ इस अनुच्छेद का अनुवाद किया गया है:

"निम्नलिखित वर्गों में आने वाली किसी भी आय, लाभ या लाभ को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा:

(i) न्यास या अन्य कानूनी दायित्व के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए पूर्ण रूप से धारित संपत्ति से प्राप्त कोई आय, और ऐसी संपत्ति के मामले में जो आंशिक रूप से 'ऐसे उद्देश्यों के लिए धारित की जाती है, आय का उपयोग किया जाता है, या अंततः इसके लिए आवेदन के लिए अलग रखा जाता है।"

उपधारा (3) के अंतिम पैराग्राफ द्वारा "धर्मार्थ उद्देश्य" को गरीबों की राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति के रूप में परिभाषित किया गया था, लेकिन धारा (i) या धारा (i-a) या धारा (ii) में निहित कुछ भी नहीं होगा। एक निजी धार्मिक ट्रस्ट की आय के उस हिस्से को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने का कार्य करता है जो जनता के लाभ के लिए नहीं है।

भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम 25 of 1953 की धारा 3 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, जैसा कि वे मूल रूप से खड़े थे, धारा (i)

और (i-a) को सम्मिलित कर लिया गया था। यह आम बात है कि संशोधन द्वारा, इन अपीलों में तय किए जाने वाले प्रश्न पर कोई महत्वपूर्ण असर डालने वाला कोई बदलाव नहीं किया गया है। संपत्ति से आय धारा 4(3)(i) के तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त करती है यदि दो शर्तें एक साथ मौजूद हों (i) संपत्ति न्यास या अन्य कानूनी दायित्व के तहत धारित की जाती है; और (ii) यह पूरी तरह या आंशिक रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए धारित की जाती है। निर्धारिती के पास जो इमारत है, वह ज्ञापन और संघ के लेखों के खंड 4 के आधार पर ज्ञापन और संघ के लेखों में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अपनी आय को लागू करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत है। निर्धारिती का मामला यह नहीं है कि निगमन के उद्देश्य गरीबों की राहत, शिक्षा या चिकित्सा राहत हैं, और केवल एक ही प्रश्न है कि जिसके लिए निर्धारिती को शामिल किया गया है, वे धारा 4(3) में "धर्मार्थ उद्देश्य" की अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य हैं या नहीं। निर्धारिती के प्रमुख उद्देश्य व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों को बढ़ावा देना और संरक्षित करना और भारत या उसके किसी भी हिस्से में व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के विकास में सहायता, प्रोत्साहन और बढ़ावा देना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति से, न केवल निर्धारिती के सदस्यों के हितों की सेवा करने का इरादा है, बल्कि पूरे देश के हितों की सेवा करने का भी इरादा है।

आर्थिक समृद्धि के

लिए अग्रणी व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की उन्नति या संवर्धन पूरे समुदाय के लाभ के लिए होता है। उस समृद्धि को उन लोगों द्वारा भी साझा किया जाएगा जो व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में संलग्न हैं, लेकिन इस कारण से उद्देश्य को किसी भी तरह से सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य नहीं बनाया जाता है। यह याद रखना चाहिए कि व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के संवर्धन और संरक्षण को केवल व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में लगे व्यक्तियों की गतिविधियों और हितों के संवर्धन और संरक्षण के साथ समान नहीं किया जा सकता है।

कमिशनर्स ऑफ इंग्लैंड रेवेन्यू बनाम

यॉर्कशायर एग्रीकल्चरल सोसाइटी (1) में यॉर्कशायर एग्रीकल्चरल सोसाइटी नामक एक संस्था का गठन कृषि स्टॉक, उपकरण आदि की प्रदर्शनी के लिए और कृषि के सामान्य संवर्धन के लिए वार्षिक बैठकें आयोजित करने के उद्देश्य से किया गया था। सभी पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में प्रतिस्पर्धा के लिए खुले थे, लेकिन कुछ विशेषाधिकार सोसाइटी की सदस्यता से जुड़े हुए थे। सोसाइटी की आय प्रवेश शुल्क और गेट प्राप्ति, पुरस्कारों के लिए स्थानीय सदस्यता, निवेश पर ब्याज और सदस्यों की सदस्यता से प्राप्त होती थी। कोर्ट ऑफ अपील द्वारा पाए गए तथ्यों पर यह माना गया कि सोसाइटी एक धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित की गई थी और वह उद्देश्य

सोसाइटी के सदस्यों द्वारा प्राप्त आकस्मिक लाभों के बावजूद जारी रहा; और उन लाभों ने सोसाइटी को "केवल धर्मार्थ उद्देश्य के लिए" स्थापित होने से नहीं रोका।

हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, तीसरा संस्करण, खंड 4 पृष्ठ 236 पर, कला। 517 में, यह कहा गया है:

"एक संघ या संस्था अपने मुख्य धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करने के क्रम में अपने सदस्यों को लाभान्वित कर सकती है और यह अकेले इसे एक धर्मार्थ उद्देश्य होने से नहीं रोकेगा। यह एक तथ्य का प्रश्न है कि क्या समाज या व्यक्तियों के निकाय के सदस्यों के लिए इतना व्यक्तिगत लाभ, बौद्धिक या पेशेवर है कि उसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता है।"

इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स बनाम द कमिश्नर्स ऑफ इंग्लैंड रेवेन्यू (2) में यह माना गया था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स की स्थापना और निगमन रॉयल चार्टर द्वारा यांत्रिक विज्ञान की सामान्य उन्नति के लिए किया गया था, और विशेष रूप से उस ज्ञान के अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए जो एक सिविल इंजीनियर के पेशे का गठन करता है, वह एक ऐसा निकाय था जो केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था। विशेष आयुक्तों ने विशेष रूप से 1922 के पूरक चार्टर के

प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा कॉर्पोरेट सदस्यता को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया था जो सिविल इंजीनियरिंग के पेशे में थे, यह माना कि संस्था केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ही स्थापित की गई थी।

उपरोक्त मामलों में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि एक संस्था या संघ को केवल इसलिए धर्मार्थ नहीं माना जाएगा कि वह अपने सदस्यों को कुछ आकस्मिक लाभ प्रदान करता है। यह एक तथ्य का प्रश्न है कि क्या मुख्य उद्देश्य धर्मार्थ प्रकृति का है और क्या आकस्मिक लाभ इतने बड़े नहीं हैं कि वे मुख्य उद्देश्य को प्रभावित करें। निर्धारिती के मामले में यह स्पष्ट है कि मुख्य उद्देश्य उपरोक्त मामलों में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि एक संस्था या संघ को केवल इसलिए धर्मार्थ नहीं माना जाएगा कि वह अपने सदस्यों को कुछ आकस्मिक लाभ प्रदान करता है। यह एक तथ्य का प्रश्न है कि क्या मुख्य उद्देश्य धर्मार्थ प्रकृति का है और क्या आकस्मिक लाभ इतने बड़े नहीं हैं कि वे मुख्य उद्देश्य को प्रभावित करें। निर्धारिती के मामले में यह स्पष्ट है कि मुख्य उद्देश्य व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के संवर्धन और संरक्षण के लिए है जो एक सामान्य सार्वजनिक उद्देश्य है। यदि संस्था के सदस्यों को कोई आकस्मिक लाभ मिलता है, तो भी वह संस्था को धर्मार्थ होने से नहीं रोकेगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स बनाम द कमिश्नर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू के मामले में यह माना

गया था कि संस्था केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई थी, भले ही इसके सदस्यों को पेशेवर लाभ प्राप्त हुए हों।

भारत के व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के संवर्धन में जनता की गहरी रुचि है और यदि निर्धारिती की गतिविधियों से वह उद्देश्य प्राप्त होता है, तो यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(3)(i) के अर्थ के भीतर होगा। सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी उद्देश्य की उन्नति।

धारा 4(3) के अंतिम पैराग्राफ को अधिनियमित करते समय विधायिका ने बहुत अधिक परिमाण की भाषा का प्रयोग किया है। "धर्मार्थ उद्देश्य" में केवल गरीबों की राहत, शिक्षा और चिकित्सा राहत ही शामिल नहीं है, बल्कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों की उन्नति भी शामिल है। खंड का उद्देश्य अधिनियम के लिए "धर्मार्थ उद्देश्य" अभिव्यक्ति की एक विशेष परिभाषा के रूप में कार्य करना है: यह फिर से समावेशी है, विशिष्ट या अनन्य नहीं है।

यहां तक अगर वस्तु या उद्देश्य को गरीबों को राहत देने या शिक्षा या चिकित्सा राहत की उन्नति के लिए प्रवृत्त नहीं होने के कारण अपने लोकप्रिय अर्थ में धर्मार्थ नहीं माना जा सकता है, तो भी इसे "धर्मार्थ उद्देश्य" अभिव्यक्ति में शामिल किया जाएगा यदि यह सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। हालांकि, "सामान्य

सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य" अभिव्यक्ति केवल पूरे मानव जाति के लिए लाभदायक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। जनता के एक वर्ग के लिए लाभदायक वस्तु सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य है। किसी धर्मार्थ उद्देश्य की सेवा के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि उद्देश्य पूरे मानव जाति या किसी विशेष देश या प्रांत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को लाभान्वित करना हो। यह पर्याप्त है यदि इरादा निर्दिष्ट व्यक्तियों से अलग जनता के एक वर्ग को लाभान्वित करना है। आयकर आयुक्त, बम्बई प्रेसीडेंसी, सिंध और बलूचिस्तान बनाम ग्रेन मर्चेन्ट्स' एसोसिएशन ऑफ बम्बई (1) में यह कहा गया था कि "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य एक सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य है जो जनता के किसी भी वर्ग से अलग सामान्य जनता के लिए उपलब्ध है और एक संघ के उद्देश्य "सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों को लाभान्वित करने के लिए जो जनता के एक वर्ग, यानी वाणिज्य में रुचि रखने वालों तक सीमित हैं" सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य नहीं हैं।

लाभान्वित होने के लिए मांगे गए समुदाय के अनुभाग को निस्संदेह सार्वजनिक या अवैयक्तिक प्रकृति के कुछ सामान्य गुणों द्वारा पर्याप्त रूप से परिभाषित और पहचान योग्य होना चाहिए: जहां संभावित लाभार्थियों को एक वर्ग में एकजुट करने वाला कोई सामान्य गुण नहीं है, उसे मान्य नहीं माना जा सकता है। यह सच है कि इस मामले में निर्धारिती के स्वामित्व

वाली इमारत से प्राप्त आय के संबंध में वास्तव में कोई ट्रस्ट नहीं है। लेकिन संपत्ति और उससे प्राप्त आय एक कानूनी दायित्व के तहत रखी जाती है, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारिती को अपने नाम से "सीमित" शब्द का उपयोग करने से बाहर करने के लिए दी गई अनुमति की शर्तों के अनुसार, और ज्ञापन और संघ के खंड 4 की स्पष्ट शर्तों के अनुसार संपत्ति और उसकी आय का उपयोग केवल ज्ञापन और संघ में निर्धारित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। राजस्व के वकील ने दलिल पेश की कि निर्धारिती के उद्देश्य अस्पष्ट और अनिश्चित हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि एक सक्षम न्यायालय को ज्ञापन और संघ द्वारा लगाए गए दायित्व को प्रशासित करने के लिए कहा जाता है, जैसा कि इसे कहा जा सकता है, तो न्यायालय उद्देश्यों की अस्पष्टता के कारण ऐसा करने से मना कर देगा, और इसलिए उद्देश्यों को धर्मार्थ नहीं माना जा सकता है। वैकल्पिक रूप में, वकील ने तर्क दिया कि ज्ञापन और संघ द्वारा विचार किए गए लाभ जनता को सामान्य रूप से लाभ नहीं थे, बल्कि इसके सदस्यों को अपने व्यवसाय को अधिक लाभप्रद रूप से चलाने के लिए लाभ था। इसके अलावा वैकल्पिक रूप से, ज्ञापन और संघ के खंड 3 (g) पर भरोसा करते हुए, वकील ने तर्क दिया कि निर्धारिती के उद्देश्य राजनीतिक थे, क्योंकि निर्धारिती के लिए पूरी आय को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विनियोजित करना खुला था। लेकिन निर्धारिती के प्राथमिक उद्देश्य व्यापार,

वाणिज्य और उद्योगों को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है और व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के विकास में सहायता, प्रोत्साहन और प्रवर्तन करना है और भारत या उसके किसी भी भाग के सामान्य वाणिज्यिक हितों की रक्षा करना है। ये उद्देश्य अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं हैं।

सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुओं के रूप में परिमित। सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की एक वस्तु, जैसे व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों का संवर्धन, संरक्षण, सहायता और प्रोत्साहन, वैध होने के लिए उन तरीकों या चरणों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिनके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त या सुरक्षित किया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि किसी संस्था को प्रशासित करने के लिए कहा जाए जिसके उद्देश्य निर्धारित प्रकृति के हैं, तो न्यायालय केवल इस आधार पर ऐसा करने से इनकार कर देगा कि जिस तरीके से व्यापार, वाणिज्य या उद्योग को बढ़ावा दिया जाना है या संरक्षित किया जाना है, सहायता या प्रोत्साहन दिया जाना है या भारत के सामान्य वाणिज्यिक हितों की रक्षा की जानी है, उन्हें निर्दिष्ट नहीं किया गया है। रंचोददास बनाम पार्वती भाई (1) जैसे मामलों की सादृश्य जिसमें प्रिवी काउंसिल ने "धर्म" के पक्ष में एक वसीयत के तहत एक उपहार को शून्य घोषित किया, भ्रामक है। उस मामले में उपहार को शून्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि न्यायिक समिति की दृष्टि में "धर्म" अभिव्यक्ति कानून, सद्गुण,

कानूनी या नैतिक कर्तव्य होने के कारण अदालतों के लिए लागू करने के लिए बहुत सामान्य और बहुत अनिश्चित थी। कमिशनर्स ऑफ इंग्लैंड रेवेन्यू बनाम नेशनल एंटी-विविसेक्शन सोसाइटी (2) में लॉर्ड सिमंड्स द्वारा टिप्पणियां कि "एक परीक्षा, और एक महत्वपूर्ण परीक्षा, क्या एक ट्रस्ट धर्मार्थ है, यह अदालत की क्षमता में निहित है कि वह इसे नियंत्रित और सुधार करे। कि यह राजा है जो रूप में धर्मार्थ का संरक्षक है, और यह कि यह उसके महान्यायवादी का अधिकार और कर्तव्य है कि वह हस्तक्षेप करे और सूचित करे" अदालत अगर एक धर्मार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी अपने कर्तव्य से कम हो जाते हैं। इसी तरह, यदि आवश्यक हो, तो एक धर्मार्थ ट्रस्ट के निष्पादन के लिए एक योजना के निर्माण में अदालत की सहायता करना भी उनका कर्तव्य है। लेकिन क्या एक क्षण के लिए यह माना जाएगा कि यह राजा की ओर से महान्यायवादी का कार्य है कि वह हस्तक्षेप करे और मांग करे कि एक ट्रस्ट स्थापित और अदालत द्वारा प्रशासित किया जाए, जिसका उद्देश्य कानून को इस तरह से बदलना है जो अत्यधिक हानिकारक हो, जैसा कि वह और महामहिम की सरकार सोच सकती है, राज्य के कल्याण के लिए?" राजस्व के मामले में मदद नहीं करते। लॉर्ड सिमंड्स की दृष्टि में ट्रस्ट का उद्देश्य राजनीतिक था, और इसलिए शून्य था, न कि इसलिए कि यह अस्पष्ट या अनिश्चित था।

बैडिली और अन्य (न्यूटाउन ट्रस्ट के ट्रस्टी) बनाम

कमिशनर्स ऑफ इंग्लैंड रेवेन्यू (3) में दो संदेशों द्वारा ट्रस्टियों को कुछ संपत्तियां हस्तांतरित की गई थीं, एक मामले में ट्रस्ट पर, अन्य बातों के साथ-साथ, धार्मिक, सामाजिक और शारीरिक के संवर्धन के लिए वेस्ट हैम और लेयटन के काउंटी बोरो में रहने वाले व्यक्ति धार्मिक सुविधाओं के प्रावधान द्वारा (1) एलआर 26 आईए 71 (2) 28 टीसी 311, 367 (3) 35 टीसी 661 इन मामलों में यह माना गया था कि ये ट्रस्ट केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नहीं थे। यह मामला 1891 के स्टांप अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ था, और यह तर्क दिया गया था कि ट्रस्ट धर्मार्थ होने के कारण कम दर पर स्टांप शुल्क देय था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि ट्रस्ट धर्मार्थ नहीं था। लॉर्ड सिमंड्स ने कहा कि "समुदाय या उसके किसी भी हिस्से का नैतिक, सामाजिक और शारीरिक कल्याण परोपकार और परोपकार का एक प्रशंसनीय उद्देश्य है, लेकिन इसका दायरा उन उद्देश्यों को शामिल करने के लिए बहुत व्यापक है जिन्हें कानून धर्मार्थ मानता है। हमारे विचार में, इन मामलों का निर्धारिती के ज्ञापन और संघ में उपयोग की गई भाषा की व्याख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह तर्क कि

निर्धारिती की धनराशि का उपयोग केवल आंध्र प्रदेश में सदस्यों या व्यापार वर्ग के लाभ के लिए किया जा सकता है, परीक्षा में खरा नहीं उतरता। ज्ञापन और संघ के पैराग्राफ 3 में विविध खंडों से यह स्पष्ट है कि उद्देश्य केवल निर्धारिती के सदस्यों या आंध्र प्रदेश के व्यापारिक समुदाय को लाभ पहुंचाना नहीं था। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सदस्यता खंड पर भरोसा किया गया था और यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल तेलुगु भाषा बोलने वाले और आंध्र प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति [आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के खंड 1 (s) में परिभाषित के रूप में] सदस्य हो सकते हैं। लेकिन यह तर्क पूरी तरह से निराधार है। खंड 5 के उप-खंड (iii) के अनुसार, भारतीय व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की रक्षा और संवर्धन करने वाली एक चैंबर ऑफ कॉमर्स या ट्रेड एसोसिएशन चैंबर की सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र है और ऐसी चैंबर ऑफ कॉमर्स या ट्रेड एसोसिएशन के प्रतिनिधि के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह तेलुगु बोल और लिख सके। इसी तरह, उप-खंड (iv) के अनुसार, आंध्र प्रदेश में अपना प्रधान कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय रखने वाली कंपनी या निगम या आंध्र प्रदेश में एक शाखा किसी

पारंपरिक या कॉर्पोरेट नाम में सदस्य बनने के लिए पात्र है और ऐसी कंपनी या निगम के प्रतिनिधि के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह तेलुगु बोल और लिख सके। पुनः उप-खंड (v) के तहत एक "निजी भागीदारी चिंता" या "संयुक्त परिवार व्यवसाय" की फर्म का एक भागीदार आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं, सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। इन सभी उप-खंडों से यह स्पष्ट है कि सदस्यता किसी भी तरह से आंध्र प्रदेश के निवासियों या तेलुगु भाषी व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। इस प्रकार, यह तर्क कि निर्धारिती के उद्देश्य केवल आंध्र प्रदेश के सदस्यों या व्यापार वर्ग के लाभ के लिए हैं, अमान्य है। किसी भी चिंता, या एकमात्र स्वामित्व वाली चिंता जिसका प्रधान कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय आंध्र प्रदेश में है या आंध्र प्रदेश में एक शाखा है, चेंबर की सदस्यता के लिए पात्र है और ऐसे सदस्य के प्रतिनिधि को तेलुगु बोलने या लिखने में सक्षम होना आवश्यक नहीं है। अंत में, उप-खंड (vi) के अनुसार, भारत में कहीं भी रहने वाला व्यक्ति और किसी भी प्रकार से व्यापार, उद्योग और वाणिज्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति चेंबर की सदस्यता के लिए पात्र है, बशर्ते कि उसकी मातृभाषा तेलुगु

हो या वह तेलुगु बोल और लिख सकता हो। सदस्यता योग्यता पर कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, न ही तेलुगु बोलने या लिखने की क्षमता के बारे में कोई सीमा है। हमें यह मानते हुए नहीं लिया जाना चाहिए कि यदि ऐसे प्रतिबंध होते, तो धर्मार्थ उद्देश्यों की उन्नति के लिए एक संस्था के रूप में निर्धारिती का चरित्र आवश्यक रूप से प्रभावित होता ज्ञापन और संघ के खंड 3(g) जिस पर दृढ़ता से भरोसा किया गया था, वह इस प्रकार है:

"व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण को प्रभावित करने वाले विधायी और अन्य उपायों को आग्रह करना या विरोध करना और व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण को प्रभावित करने वाले कानून और व्यवहार में बदलाव लाना और विशेष रूप से उन व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों को प्रभावित करना जिनमें आंध्र शामिल हैं और सभी को प्राप्त करना स्वीकृत साधनों द्वारा, जहाँ तक संभव हो, व्यापारियों को एक समूह के रूप में और सामान्य रूप से वाणिज्यिक हितों को प्रभावित करने वाली सभी शिकायतों को दूर करना।"

लेकिन खंड 3(g) निर्धारिती का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है: यह केवल

व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के संवर्धन या संरक्षण, या व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के विकास में सहायता, प्रोत्साहन और प्रवर्तन या सामान्य वाणिज्यिक हितों की रक्षा और संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्यों के लिए आकस्मिक है। धारा 4(3)

में "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य" अभिव्यक्ति में प्रथम दृष्टया वे सभी उद्देश्य शामिल होंगे जो आम जनता के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि केवल एक उद्देश्य धर्मार्थ होना बंद हो जाएगा, भले ही सार्वजनिक कल्याण की सेवा करने का इरादा हो, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण को प्रभावित करने वाले कानून का आग्रह करने या विरोध करने के लिए कदम उठाना शामिल है। यदि प्राथमिक उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों की उन्नति है, तो वह धर्मार्थ बना रहेगा, भले ही उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में एक आकस्मिक प्रवेश, जैसे कि उस उद्देश्य से संबंधित कानून का प्रचार या विरोध करना, परिकल्पित हो। इन द ट्रस्टियों ऑफ द ट्रिब्यून(1) में, यह माना गया था कि एक ट्रस्ट, जिसका उद्देश्य एक समाचार पत्र का प्रकाशन था, एक धर्मार्थ ट्रस्ट था, भले ही समाचार पत्र में कभी-कभी राजनीतिक मुद्दों पर लेख होते थे।

इसलिए, हम इस

निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निर्धारिती के उद्देश्य धर्मार्थ उद्देश्य हैं और वह धारा 4(3) के अर्थ के भीतर एक धर्मार्थ संस्था है।

प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को यह विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या किसी वसीयत के तहत बनाया गया ट्रस्ट, जो एक प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्र को कुशल स्थिति में बनाए रखने और समाचार पत्र की उदार नीति को बनाए रखने के लिए था, प्रेस और समाचार पत्र की अधिशेष आय को सभी वर्तमान खर्चों को पूरा करने के बाद समाचार पत्र को बेहतर बनाने और इसे स्थायी आधार पर रखने में खर्च करता है और आगे यह भी प्रदान करता है कि यदि समाचार पत्र कार्य करना बंद कर देता है या किसी अन्य कारण से आय के अधिशेष को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, तो इसे उसी वसीयतकर्ता द्वारा बनाए गए किसी अन्य ट्रस्ट के धन से स्थापित किए गए कॉलेज के रखरखाव के लिए लागू किया जाएगा, धारा 4(3) के अर्थ में एक धर्मार्थ उद्देश्य था।

न्यायिक समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि सेटलर का उद्देश्य प्रांत को शिक्षित जनमत के एक अंग के साथ आपूर्ति करना था और यह प्रथम दृष्टया सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का एक उद्देश्य था, और कहा:

"ये अंग्रेजी निर्णय इस हद तक ही प्रासंगिक हैं कि वे इस बात को दर्शाते हैं कि जिस तरीके से राजनीतिक उद्देश्य, व्यापक अर्थों में जिसमें विशेष कारणों के हित में कानून बनाने के लिए परियोजनाएं शामिल हैं, इस सवाल को प्रभावित करते हैं कि क्या न्यायालय एक ट्रस्ट को सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का मान सकता है। मूल रेफरल पत्र में आयुक्त ने यह सुझाव नहीं दिया था कि समाचार पत्र का इरादा इसके संस्थापक द्वारा केवल राजनीतिक प्रचार का एक वाहन बनना था, और सरदार दयाल सिंह के मामले में यह संदेह करना अनुचित लगता है कि उनका उद्देश्य एक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रदान करके उत्तर भारत के लोगों को लाभान्वित करना था - समाचारों का प्रसार और जनहित के सभी मामलों पर राय व्यक्त करना। हालांकि शायद असंभव नहीं है, लेकिन एक समाचार पत्र के लिए किसी विशेष राजनीतिक रंग को प्राप्त करने या रखने से बचना मुश्किल है, जब तक कि वह सरकारों या विधानसभाओं की गतिविधियों के सभी संदर्भों से बचता है या उनका इलाज एक उदार या असंगत तरीके से करता है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में उत्तर भारत की परिस्थितियां निस्संदेह किसी भी भारतीय पाठकों के लिए प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र को सामाजिक और राजनीतिक सुधार के विभिन्न आंदोलनों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बना देंगी। लेकिन उनके लॉर्डशिप के पास सामग्री होने के कारण जो समाचार पत्र के चरित्र को दर्शाती है जैसा कि यह वास्तव में

वसीयतकर्ता के जीवनकाल में संचालित किया गया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राजनीति और कानून के प्रश्न समाचार पत्र के संचालन के अधीनस्थ थे और एक साधन थे जिसके द्वारा इसका मुख्य उद्देश्य, जो कि जनता को सूचित करना और शिक्षित करना था, प्राप्त किया जाना था।

ऑल इंडिया

स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम-टैक्स, बॉम्बे (1) मामले में निर्धारिता का गठन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक प्रस्ताव द्वारा हाथ से कताई और हाथ से बुनाई के ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए एक अपंजीकृत संघ के रूप में किया गया था। एसोसिएशन को कांग्रेस संगठन के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन इसका स्वतंत्र अस्तित्व और शक्तियां थीं जो राजनीति से अप्रभावित और अनियंत्रित थीं। एसोसिएशन के उद्देश्यों में, अन्य बातों के अलावा, ऋण, उपहार या बक्षीस के रूप में खादी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, हाथ से कताई सिखाई जाने वाले स्कूलों या संस्थानों की मदद करना या स्थापित करना, खादी भंडारों की मदद करना और खोलना, खादी सेवा स्थापित करना, कांग्रेस की ओर से एजेंसी के रूप में कार्य करना शामिल था। चरखा और हथकरघे खरीदे गए और निवासियों को निःशुल्क आपूर्ति की गई। गरीब लोगों को कपास की आपूर्ति की गई ताकि वह सूत में कताई जा सके और इस प्रकार काता हुआ सूत और एसोसिएशन द्वारा

अधिग्रहित सूत अन्य गरीब लोगों को हाथ से बुनाई के लिए आपूर्ति की गई। आयकर आयुक्त द्वारा एसोसिएशन की आय को भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 4(3)(i) के तहत छूट प्राप्त न होने के रूप में माना गया था, क्योंकि (i) एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक था, (ii) भले ही यह राजनीतिक न हो, प्रमुख उद्देश्य किसी भी स्थिति में कानून में वैध धर्मार्थ उद्देश्य नहीं था, और (iii) कुछ उद्देश्य स्पष्ट रूप से धर्मार्थ उद्देश्य नहीं थे। न्यायिक समिति ने माना कि एसोसिएशन की आय पूरी तरह से धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट या अन्य कानूनी दायित्व के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त हुई थी और दान के कानून पर अंग्रेजी निर्णय निश्चित और सटीक वैधानिक प्रावधानों पर आधारित नहीं थे, जो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 4(3)(i) के प्रावधानों की व्याख्या करने में सहायक नहीं थे। धारा 4(3) के शब्द पेमेल बनाम कमिश्नर फॉर स्पेशल पर्पस ऑफ इनकम-टैक्स (1) मामले में लॉर्ड मैकनागन द्वारा धर्मार्थ की परिभाषा से काफी प्रभावित थे, लेकिन उस परिभाषा का कोई वैधानिक आधार नहीं था।

न्यायिक समिति ने यह भी माना कि एसोसिएशन का राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, भले ही वह कांग्रेस संगठन का एक अभिन्न अंग था। एसोसिएशन के उद्देश्य ग्रामीण उद्योग के विकास में मदद करना और गरीबों को लाभान्वित करना था, और यह कि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक साधनों का उपयोग

नहीं करता था।

इसलिए, न्यायिक समिति ने यह माना कि एसोसिएशन की आय धारा 4(3)(i) के अर्थ में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए प्राप्त हुई थी और इस प्रकार आयकर से छूट प्राप्त थी। न्यायिक

समिति ने यह भी माना कि भारतीय विधायिका ने "धर्मार्थ उद्देश्य" अभिव्यक्ति की एक परिभाषा विकसित की है जो पेमसेल मामले (1) में न्यायिक रूप से प्रदान की गई परिभाषा से अपने भौतिक खंड में विचलित होती है, और अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णय, जो भारतीय कानून से भिन्न भाषा की व्याख्या पर आधारित हैं, का बहुत कम मूल्य है। इसलिए, हम बार में उद्धृत अंग्रेजी मामलों की बड़ी संख्या से निपटने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, सिवाय तीनों का उल्लेख करने के, जिन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ट्रस्टों को अवैध घोषित किया। रेक्स बनाम

द स्पेशल कमिश्नर ऑफ इनकम-टैक्स (एक्स-पार्टे द हेडमास्टर्स कॉन्फ्रेंस) और रेक्स बनाम द स्पेशल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (एक्स-पार्टे) द इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ प्रिपरेटरी स्कूल (1) मामलों में यह माना गया था कि कंपनी अधिनियम के तहत एक गारंटी द्वारा सीमित एक एसोसिएशन के रूप में शामिल हेडमास्टर्स का एक सम्मेलन, जिसके तहत ज्ञापन और संघ के तहत आय को उसके व्यक्ति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लागू किया जाना था, जिनमें से एक विधायी या प्रशासनिक शैक्षिक उपायों

को बढ़ावा देना या विरोध करना, परीक्षाएं आयोजित करना आदि था, आयकर अधिनियम के अर्थ में केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित व्यक्तियों का एक निकाय नहीं था। इसी तरह, कंपनी अधिनियम के तहत एक गारंटी द्वारा सीमित एक एसोसिएशन के रूप में शामिल प्रिपरेटरी स्कूलों का एक सम्मिलित संघ, जिसके तहत ज्ञापन और संघ के तहत आय को उसके व्यक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लागू किया जाना था, जिनमें से एक विधायी या प्रशासनिक शैक्षिक उपायों को बढ़ावा देना या विरोध करना, परीक्षाएं आयोजित करना आदि था, आयकर अधिनियम के अर्थ में केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित व्यक्तियों का एक निकाय नहीं था।

न्यायिक समिति ने इन मामलों को निम्नलिखित आधार पर प्रतिष्ठित किया:

- उन मामलों में, निर्धारितियों के प्राथमिक उद्देश्य विधायी या प्रशासनिक उपायों को बढ़ावा देना या विरोध करना था, जबकि निर्धारिती का प्राथमिक उद्देश्य गरीबों को राहत प्रदान करना और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना था।
- उन मामलों में, निर्धारितियों के राजनीतिक उद्देश्य थे, जबकि निर्धारिती के राजनीतिक उद्देश्य नहीं थे।

इसलिए, न्यायिक समिति ने यह माना कि निर्धारिती की आय भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 4(3)(i) के अर्थ में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए प्राप्त हुई थी और इस प्रकार आयकर से छूट प्राप्त थी।

इस मामले में, न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या एक एसोसिएशन, जिसका आय उसके व्यक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लागू किया जाना था, जिसमें विधायी या प्रशासनिक शैक्षिक उपायों को बढ़ावा देना या विरोध करना शामिल था, एक धर्मार्थ संस्था थी और उसकी आय धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू की जा सकती थी।

न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि इसी तरह के मामलों में अंग्रेजी न्यायालयों ने माना था कि यदि आय विधायी या प्रशासनिक शैक्षिक उपायों को बढ़ावा देने या विरोध करने के लिए उपयोग की जा सकती है, तो यह केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू होने वाली आय नहीं है।

न्यायालय ने यह भी माना कि एक ट्रस्ट जिसका उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, उसे हमेशा अमान्य माना गया है, न कि इसलिए कि वह अवैध है, बल्कि इसलिए कि न्यायालय के पास यह आंकने का कोई साधन नहीं है कि कानून में प्रस्तावित परिवर्तन जनहित में होगा या नहीं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक हालिया निर्णय में, लक्ष्मण बालवंत

भोपतकर बनाम चैरिटी कमिश्नर, बॉम्बे (1) मामले में इस बात पर विचार किया कि क्या बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 की धारा 9 (4) में अभिव्यक्ति "किसी अन्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य की उन्नति के लिए" के अर्थ के भीतर, जनता की राय को शिक्षित करना और लोगों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना एक धर्मार्थ उद्देश्य के लिए एक ट्रस्ट था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना (न्यायमूर्ति सुब्बा राव असहमति व्यक्त करते हुए) कि जिस उद्देश्य के लिए ट्रस्ट की स्थापना की गई थी वह राजनीतिक था, और राजनीतिक उद्देश्य एक धर्मार्थ उद्देश्य नहीं था।

इसलिए, न्यायालय ने इस मामले में यह माना कि एसोसिएशन की आय धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू नहीं की जा सकती थी और इसलिए वह आयकर से छूट प्राप्त करने के हकदार नहीं थी।

इस मामले में, न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या एक एसोसिएशन, जिसका एक उद्देश्य विधायी और अन्य उपायों को प्रेरित करना या उनका विरोध करना था जो व्यापार, वाणिज्य या निर्माण को प्रभावित करते हैं, एक धर्मार्थ संस्था है और उसकी आय धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू की जा सकती है।

न्यायालय ने यह माना कि इसी तरह के मामलों में अंग्रेजी न्यायालयों ने माना था कि यदि किसी ट्रस्ट का प्राथमिक या मुख्य उद्देश्य

राजनीतिक है, तो वह ट्रस्ट धर्मार्थ नहीं है।

न्यायालय ने माना कि मौजूदा मामले में, निर्धारिती का प्राथमिक उद्देश्य विधायी और अन्य उपायों को प्रेरित करना या उनका विरोध करना नहीं था जो व्यापार, वाणिज्य या निर्माण को प्रभावित करते हैं। निर्धारिती का प्राथमिक उद्देश्य, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के विकास में सहायता करना, प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना और भारत या उसके किसी भी हिस्से के सामान्य वाणिज्यिक हितों पर नजर रखना और उनकी रक्षा करना है। केवल इन प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही यह एसोसिएशन के ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक था कि निर्धारिती विधायी और अन्य उपायों को प्रेरित करने या उनका विरोध करने के लिए कदम उठा सकता है जो व्यापार, वाणिज्य या निर्माण को प्रभावित करते हैं। ऐसी वस्तु को विशुद्ध रूप से सहायक या पुरक माना जाना चाहिए और न कि प्राथमिक वस्तु। इस प्रकार, यह अपीलें असफल होती हैं तथा कोस्ट के साथ अस्वीकार की जाती है।

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी योगेश जोशी आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।